भारत का एक सुप्रसिद्ध हिन्दी
कृषि समाचार-पत्र (न्यूज़ पेपर)

खेती दुनिया

www.khetiduniyan.in

Excellence in Agri Info
KHETI DUNIYAN

KHETI DUNIYAN, PATIALA

All Subject to Patiala Jurisdiction.

BOOK POST – PRINTED MATTER

• Issue Dated 31-08-2024 • Vol.8 No.35 • H.O. : KD Complex, Gaushala Road, Patiala-147001 (Pb.) Ph. : 0175-2214575 • Page : 08 E-mail : khetiduniyan1983@gmail.com

देश में खरीफ फसलों की बुवाई ने 1065 लाख हैक्टेयर का आंकड़ा किया पार

इस वर्ष धान की बुवाई 394.28 लाख हैक्टेयर में की गई है, जो पिछले साल के 378.04 लाख हैक्टेयर की तुलना में अधिक है

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 27 अगस्त 2024 तक की खरीफ फसलों की बुवाई की प्रगति रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कुल 1065 लाख हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फसलों की बुवाई की

गई है। इस साल खरीफ फसलों की बुवाई में कई प्रमुख फसलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार, इस वर्ष धान की बुवाई 394.28 लाख हैक्टेयर में की गई है, जो पिछले साल के 378.04 लाख हैक्टेयर की तुलना में अधिक है। इसी तरह, दलहन की बुवाई 122.16 लाख हैक्टेयर में की गई है, जो पिछले साल के 115.55 लाख हैक्टेयर से ज्यादा है। मोटे अनाज की खेती भी 185.51 लाख हैक्टेयर में की गई है, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 177.50 लाख हैक्टेयर था। तिलहन की बुवाई में भी मामूली वृद्धि दर्ज की गई है, इस वर्ष 188.37 लाख हैक्टेयर में तिलहन की खेती हुई है, जो पिछले साल 187.36 लाख हैक्टेयर थी। गन्ने की बुवाई 57.68 लाख हैक्टेयर में की गई है, जो पिछले साल के 57.11 लाख हैक्टेयर से अधिक है।

हालांकि, जूट और मेस्टा की बुवाई में इस वर्ष कुछ कमी आई है, जहां पिछले साल 6.56 लाख हैक्टेयर में बुवाई हुई थी, वहीं इस साल 5.70 लाख हैक्टेयर में बुवाई की गई है। कपास की बुवाई भी इस वर्ष 111.39 लाख हैक्टेयर में की गई है, जो पिछले साल के 122.74 लाख हैक्टेयर से कम है। कुल मिलाकर, खरीफ फसलों की बुवाई का यह सीजन भारतीय कृषि के लिए सकारात्मक संकेत दे रहा है, जिसमें विभिन्न फसलों की खेती में वृद्धि देखी गई है।

किसान मेले

नागकलां (अमृतसर)	3 सितम्बर
बल्लोवाल सौंखड़ी	6 सितम्बर
फरीदकोट	10 सितम्बर
गुरदासपुर	18 सितम्बर
रौणी (पटियाला)	24 सितम्बर
बठिण्डा	27 सितम्बर

पी.ए.यू. कैम्पस, लुधियाना
13 से 14 सितम्बर, 2024

खेती दुनिया द्वारा इन मेलों पर स्टाल लगाए जाएंगे और नई मैंबरशिप हेतु बुकिंग की जाएगी।

चौ. चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार
16 से 17 सितम्बर, 2024

लगातार किसानों की तरफ से ज्यादा स्प्रे होने की वजह से प्रभावित हो रही थी फसल

पंजाब सरकार ने बासमती में 10 कीटनाशकों के स्प्रे पर लगाया प्रतिबंध, ताकि विदेशी नकार न

पिछले कई वर्षों से पंजाब की बासमती पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में कई बार विदेश में बासमती के सैंपल फेल होने से नकारा गया है।

वजह किसानों की तरफ से फसल पर कीटनाशकों का प्रयोग ज्यादा मात्रा में होना। ऐसे में अब सरकार ने खरीफ सीज़न में 10 कीटनाशक दवाइयों को प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है ताकि कीटनाशक स्प्रे का फसल पर अधिक मात्रा में प्रयोग न कर सके। सरकार की तरफ से खरीफ सीज़न में 10 कीटनाशकों में कार्बान्डाज़िम, क्लोरोपायरीफॉस, ट्राईसाइक्लाजोल, एसीफेट, थाइमैथोक्सम, बुफ्रोजिन, इमिडाक्लोप्रिड, प्ररीपिकोनाजोल, हैक्साकोनाजोल व प्रोफिनोफॉस ट्राइजोफॉस, थायोफ्नेट मिथाइल शामिल है। ज़िला खेतीबाड़ी अफसर डॉ. प्रकाश सिंह ने बताया कि इस बार लुधियाना में 2 लाख 56 हज़ार 500 हैक्टेयर एरिया में धान व बासमती की बुवाई की गई है। इसमें 12 हज़ार 500 हैक्टेयर एरिया में बासमती आती है।

उन्होंने कहा कि लुधियाना के साथ लगते कई गांवों में कैंप लगाकर किसानों को जरूरत से ज्यादा स्प्रे न करने की हिदायत दी जा रही है ताकि बासमती को बचाया जा सके। पी.ए.यू. के एंटोमोलॉजी विभाग के कीट विज्ञानी डॉ. कमलजीत सिंह सूरी ने बताया कि इससे पहले भी 2012 में यूनाइटेड स्टेट अमरीका व इरान ने खाने लायक न बताकर बासमती को नकार दिया था। इसके बाद खेतीबाड़ी विभाग ने किसानों पर सख्ती करके कीटनाशकों के स्प्रे करने पर ब्रेक लगाई। लेकिन 2017 व 2018 में एक बार फिर से बासमती के सैंपल फेल होने से बासमती को नकारा गया, लेकिन 2020 के बाद बासमती के सैंपल पास हो रहे है। अभी सरकार की तरफ से केवल 60 दिन के लिए ही प्रतिबंध लगाया जा रहा है। लेकिन कृषि विभाग ने केन्द्र सरकार से अपील की है कि 60 दिन की जगह 90 दिन किया जाए ताकि बासमती को बचाने में फायदा मिल सके। उन्होंने कहा कि किसानों को हर साल फसल पर जरूरत अनुसार ही कीटनाशक स्प्रे करने के साथ ही बढ़िया किस्म की खाद डालने के लिए जागरूक किया जाता है।

2017 में स्वीडन, फिनलैंड और नार्वे ने लौटाए थे बासमती के 24 कंटेनर

वर्ष 2017 में खरीफ सीज़न की बासमती के स्वीडन, फिनलैंड और नार्वे ने 24 कंटेनर लौटा दिए थे। जब विदेश में बासमती को टैस्ट किया गया, तो खाद का कम प्रयोग व कीटनाशकों का जरूरत से ज्यादा प्रयोग होना पाया गया था। पी.ए.यू. के इंटोमॉलोजी डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल डॉ. कमलजीत सिंह सूरी ने बताया कि बासमती की 32 वैरायटी पाई जाती है, लेकिन उसमें 5 वैरायटी ऐसी है, जिनकी विदेशों में ज्यादा डिमांड होने के कारण एक्सपोर्ट की जाती है, जिसमें पूसा बासमती-1121, 1509, पूसा-1401, ताराओरी (एच.बी.सी.-19) व सुपर (सहाबनम) शामिल है। लेकिन किसानों की तरफ से बासमती की फसलों पर ज्यादा कीटनाशक स्प्रे होने की वजह से इन वैरायटी को भी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है।

पेंशन की भांति किसान को सुनिश्चित कीमत क्यों नहीं

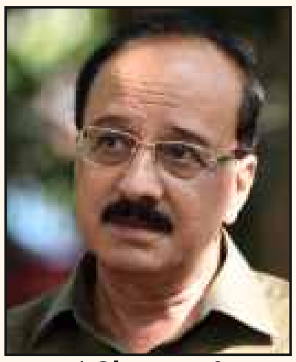

देविंदर शर्मा
कृषि एवं खाद्य विशेषज्ञ

इसे 'पेंशन सुधार' बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है। उन्होंने कहा 'हमें उन सभी सरकारी कर्मचारियों की कड़ी मेहनत पर गर्व है जो राष्ट्रीय प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।' वास्तव में, यूपीएस, जो प्राप्त अंतिम वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन का आश्वासन देता है स्वीकारोक्ति है कि पहले वाली और बाजार नीत महंगाई से जुड़ी न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) सरकारी कर्मचारियों के लिए कारगर नहीं रही। सरकारी कर्मचारियों के लिए 'परिभाषित लाभ' सुनिश्चित करने के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेंशन योजना में बदलाव किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बाजार नीत अत्याचार (महंगाई) का सामना न करना पड़े।

हालांकि, प्रधानमंत्री ने कई मौकों पर देश के किसानों की सराहना की है और अकसर कृषक समुदाय द्वारा प्रदर्शित लचीलेपन की प्रशंसा की है, लेकिन लंबे वक्त से चली आ रही गारंटीशुदा कीमत की मांग पर विचार करने में कोई भी इच्छुक नहीं है। अगर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए बाजार नीत महंगाई से निपटना मुश्किल हो रहा है, तो स्पष्ट कर दें कि बाजार नीत महंगाई किसान के लिए भी उतनी ही बड़ी समस्या है। अगर कर्मचारियों को एक सुनिश्चित पेंशन की जरूरत पड़ती है, तो किसान को भी सुनिश्चित कीमत की जरूरत है। दुनिया में कहीं भी बाजार ने किसानों के लिए उच्च आय सुनिश्चित नहीं की है। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में, या तो सब्सिडी देकर आय में घाटे की भरपाई की जाती है (चीन कृषि सब्सिडी प्रदान करने में शीर्ष पर उभरा है) या फिर कृषि को अपनी सुविधानुसार बाजार की ताकतों के रहमो-करम पर छोड़ दिया जाता है, मसलन, भारत में।

जैसा कि कुछ अध्ययनों से पता चला है, निष्कर्ष केवल यह है कि भारतीय किसान आय पिरामिड के निचले स्तर पर है, बल्कि पिछले लगभग 25 वर्षों से वे हर साल घाटा उठा रहे हैं। किसानों को कभी खत्म न होने वाली गरीबी से बाहर निकालने का एकमात्र कारगर ढंग है कृषि कीमतों की गारंटी कानूनी रूप से बाध्यकारी तंत्र बनाकर सुनिश्चित करना। परंतु इसकी परवाह न करते हुए, एनडीए सरकार ने कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट में पेश एक शपथपत्र में कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) गारंटी देने वाला कानून बाजार में 'बिगाड़ ला देगा'। अजीब बात यह है कि जब किसानों की बात आती है, तो नीति निर्माता 'बाजार में बिगाड़' का वास्ता देकर और सुनिश्चित कृषि कीमतों से महंगाई पर आगे असर का हौवा खड़ा कर देते हैं। कर्मचारियों के मामले में सुनिश्चित पेंशन से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, उनके मामले में, 'बाजार में बिगाड़' का डर अचानक गायब हो जाता है।

जब मुख्यधारा के अर्थशास्त्री मानते हैं कि कानूनन एमएसपी से उपभोक्ता कीमतें बढ़ेंगी और इस तरह 'बाजार में बिगाड़' होगा, तो वास्तव में, यह कॉर्पोरेट मुनाफे को कम करता है और इसीलिए हो-हल्ला मचता है। अजीब बात यह है कि मुक्त बाजार के हामी इन अर्थशास्त्रियों की यही नस्ल तब चुप रहती है जब अमेरिका में कॉर्पोरेट अपने उत्पाद की 'मूल्य वृद्धि' करते हैं – उपभोक्ताओं को नोच खाने के लिए कीमतों में बेजा बढ़ोतरी करते हैं। वास्तव में यह मूल्य विकृति है। अमेरिका में पहले से ही, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क सहित 38 राज्यों ने ऐसे कानून बनाए हैं जो इस चलन को प्रतिबंधित करते हैं। उदाहरणार्थ, न्यूयॉर्क राज्य ने उन कंपनियों के खिलाफ कदम उठाया जिन्होंने महामारी के दौरान हैंड सैनिटाइजर की कीमतों में 400 प्रतिशत की वृद्धि की थी। और फिर भी, कई बाजार अर्थशास्त्री साफ नजर आने वाली ऐसी बाजार विकृतियों पर अंकुश लगाने के उपायों को सोवियत शैली के मूल्य नियंत्रण की ओर वापसी करार देते हैं। बाजार के पक्ष में यह पूर्वाग्रह तब पैदा होता है जब किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की बारी आए, लेकिन तब नहीं जब कॉर्पोरेट ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए कीमतें बढ़ाते हैं। 'बाजार विकृति' पर यह दोगलापन किसानों को जीवनयापन की आय प्रदान करने की राह में अड़चन है। निरूसंदेह, किसानों को देय सुनिश्चित कीमत के अनुसार बाजार अपने आप समायोजित हो जाएंगे। यह केवल खास किस्म की विचारधारा ही है, जो अड़ंगा लगा रही है।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कॉर्पोरेट द्वारा अनाप-शनाप मूल्यवृद्धि पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया है, जो कोविड महामारी के बाद खाद्य और किराना वस्तुओं की कीमतों में आई 53 प्रतिशत वृद्धि के लिए अकेले जिम्मेदार है। रिपब्लिकनों ने उनके इस रुख को 'कम्युनिस्ट' ठहराया है। दक्षिणपंथी चाहे जो भी कहें, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, जैसा कि कुछ अर्थशास्त्री भी स्वीकारते हैं कि बेजा मूल्यवृद्धि पर अंकुश अच्छी अर्थव्यवस्था के साथ-साथ अच्छी राजनीति भी है। हैरिस ने उन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का वादा किया है जो खाद्य कीमतों को कृत्रिम रूप से ऊंचा रख रही हैं।

वापस कर्मचारियों की पेंशन पर लौटते हुए, यह देखना दिलचस्प है कि व्यय विभाग इस निर्णय को सही ठहराने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा है, इसे 'राजकोषीय रूप से विवेकपूर्ण' करार देते हुए दावा किया जा रहा है कि 'यह नागरिकों की भावी पीढ़ियों को वित्तीय कठिनाई से बचाएगा'। निश्चित रूप से, कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित पेंशन के खिलाफ कोई नहीं है। लेकिन यदि कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का आश्वासन दिया जा सकता है, तो कोई वजह नहीं है कि किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा का भरोसा न दिया जा सके। वे राष्ट्रीय प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और उनकी अथक मेहनत की बदौलत ही देश में खाद्य सुरक्षा बनी हुई है।

मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले के किसान कमलेश पाटीदार ने जब 10 एकड़ में खड़ी अपनी सोयाबीन की फसल को खुद ही रौंद दिया, तो उन्हें यह अहसास नहीं था कि इससे एक 'चेन रिएक्शन' शुरू हो जाएगा। घटना का वीडियो वायरल होने के कुछ ही दिनों बाद, कई अन्य दुखी किसानों द्वारा फसल उखाड़ने की खबरें आने लगीं। सोयाबीन की कीमतों में गिरावट- और वह भी कटाई के मौसम से डेढ़ महीने पहले- अर्थशास्त्रियों की एक और धारणा को नकारती है जो यह कहती है कि किसानों को कटाई तब तक रोक कर रखनी चाहिए जब तक कि उन्हें मंडी में फसल का भाव चढ़ा हुआ नजर न आने लगे। लेकिन यह जुगत भी कारगर न रही।

सोयाबीन की मौजूदा कीमतें 12 साल पहले के स्तर पर आ गई हैं, लेकिन कृषि पर निर्भर आजीविका के विनाश ने लाखों सोयाबीन किसानों को गुस्से से भर दिया है। कीमतें, जो एमएसपी से बहुत कम हैं, उत्पादन लागत तक निकालने के लिए भी पर्याप्त नहीं हैं। हैरानी की बात है कि हमारे पास किसानों के लिए एक सुनिश्चित मूल्य नीति कब होगी जो न केवल किसानों की भावी बल्कि वर्तमान पीढ़ी के लिए भी वित्तीय कठिनाइयों को रोकेगी। इसके तुरंत बाद, टमाटर की कीमतों में 60 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25 किलोग्राम वाले क्रेट का भाव 300 रुपये के निचले स्तर पर आने की खबरें आईं। और फिर बासमती

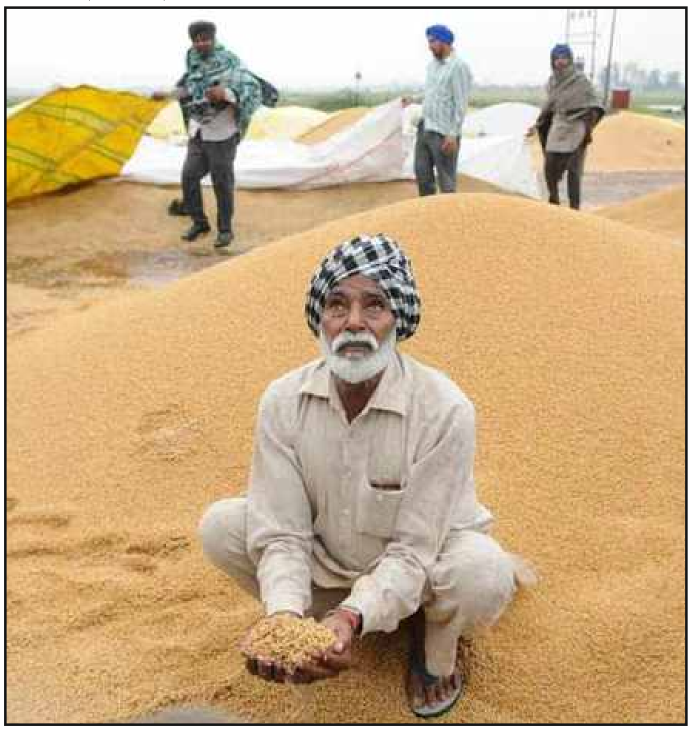

की कीमतों में 28 प्रतिशत की गिरावट के साथ 2,500 रुपये प्रति क्विंटल आने की खबरें भी आईं। यह केवल इसी साल होने वाली कोई अनोखी बात नहीं है, बल्कि यह चलन एक दर्दनाक सालाना प्रवृत्ति बन चुका है, जिसको लेकर देश में चिंता नहीं है। किसान चाहे वह हो जिसके पास विपणन योग्य अतिरिक्त उत्पाद है या फिर हाशिए पर आता कृषक, जिसको प्रत्यक्ष आर्थिक मदद दी जाती है, उन्हें कानूनन गारंटीकृत एमएसपी प्रदान करना, वह बड़ा सुधार है जिसका इंतजार कृषि को शिद्दत से है।

जैसा कि कुछ अध्ययनों से पता चला है, निष्कर्ष केवल यह है कि भारतीय किसान आय पिरामिड के निचले स्तर पर है, बल्कि पिछले लगभग 25 वर्षों से वे हर साल घाटा उठा रहे हैं। किसानों को कभी खत्म न होने वाली गरीबी से बाहर निकालने का एकमात्र कारगर ढंग है कृषि कीमतों की गारंटी कानूनी रूप से बाध्यकारी तंत्र बनाकर सुनिश्चित करना। परंतु इसकी परवाह न करते हुए, एनडीए सरकार ने कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट में पेश एक शपथपत्र में कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) गारंटी देने वाला कानून बाजार में 'बिगाड़ ला देगा'।

सुनील कुमार, विनीता राजपूत, नरेन्द्र कुमार,
ज़िला विस्तार विशेषज्ञ,
कृषि विज्ञान केन्द्र, सिरसा,
चौ. चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार

गाजरघास

हानिकारक प्रभाव और प्रबंधन

गाजरघास या पार्थेनियम को कांग्रेस घास, सफेद टोपी, चटक चाँदनी, गंधी बूटी आदि नामों से भी जाना जाता है। पहली बार इस खरपतवार का बीज वर्ष 1955 में अमेरिका से आयात किए गए गेहूं के साथ भारत में आया था। बहुत ही कम समय में विदेश से आई यह खरपतवार आज हमारे देश में लगभग 35 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र में फैल चुकी है। यह किसी भी प्रकार की मिट्टी और जलवायु में उग सकती है। इसलिए यह घास खेतों, बागों, सड़क किनारे, रेलवे लाईन के पास, बंजर भूमि व रिहायशी इलाकों, सभी जगह देखी जा सकती है। भारत में इसका प्रसार सिंचित की अपेक्षा, बारानी भूमि में अधिक देखा गया है। भारत के अलावा यह घास अमेरिका, मैक्सिको, वेस्टइंडीज़, नेपाल, चीन, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य देशों के विभिन्न भू-भागों में भी फैली हुई है।

अपने बीजों से फैलने वाली यह खरपतवार 3-4 माह में अपना जीवनकाल पूरा करती है, जिसकी लंबाई 1.5 से 2 मीटर तक होती है। एक पौधे में 5000 से 25000 बीज पैदा करने की क्षमता होती है। हल्के होने के कारण इसके बीज हवा में आसानी से इधर-उधर पहुंच जाते है, जोकि इसके देशव्यापी प्रसार का एक कारक है। इस पौधे में सेक्स्यूटरपिन लैक्टोन नामक विषाक्त पदार्थ पाया जाता है, जो फसलों के अंकुरण और उनकी बढ़वार को रोकता है, जिससे अनाज और बागवानी फसलों की उपज लगभग 40 प्रतिशत तक कम हो सकती है।

गाजरघास के दुष्प्रभाव : मनुष्य व पशुओं के स्वास्थ्य के लिए गाजर घास को बहुत खतरनाक खरपतवारों में गिना जाता है। यह मनुष्य व पशुओं में त्वचा रोग (डर्मेटाइटिस), अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का कारण बनता है। पशुओं में इसका सेवन करने से दस्त, मुंह में छाले और अत्याधिक लार की समस्या होने लगती है, जिस कारण चारे में इस घास का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

गाजरघास नियंत्रण के उपाय : गाजरघास के प्रभावशाली नियंत्रण के लिए यह उपाय किए जा सकते है :

* अपने आस-पास के क्षेत्रों को गाजरघास मुक्त रखें। सामुदायिक स्तर पर साफ-सफाई करवाते रहें। वर्षा का समय गाजरघास नियंत्रण के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। यदि इसे फूल आने से पहले नष्ट किया जाए, तो असंख्य बीज उत्पादन को रोक कर इसके जीवन-चक्र को तोड़ा जा सकता है।
* गाजर घास के दुष्प्रभाव के बारे में लोगों को संगोष्ठी, प्रशिक्षण और प्रदर्शन द्वारा जागरूक करें।
* फूल आने से पहले पौधे को नष्ट कर दें। इसके अवशेषों का स्वाद और केंचुआ खाद बनाने में प्रयोग किया जा सकता है।
* गाजर घास को विस्थापित करने के लिए चकोड़ा (कैसिया सिरेसिया या कैसिया तोरा) और गेंदा जैसे स्व-स्थाई प्रतिस्पर्धी पौधों की प्रजातियों के बीज का छिड़काव करें। यह पौधे गाजरघास के फैलाव व वृद्धि को रोकते हैं।
* वर्षा आधारित खेती वाले क्षेत्रों में जल्दी बढ़ने वाली फसलें जैसे ढैंचा, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि फसलें लेनी चाहिए।
* फसल-रहित क्षेत्रों में सभी प्रकार के खरपतवार को नष्ट करने के लिए ग्लाइफोसेट (1-1.5%) का छिड़काव करें। मिश्रित वनस्पति में सिर्फ पार्थेनियम के नियंत्रण के लिए मेट्रीब्यूजिन (0.3-0.5%) या 2,4-डी (1.0-1.5%) का छिड़काव फूल आने से पहले करें। फसलों में गाजरघास का प्रबंधन करने से पहले खरपतवार वैज्ञानिक/विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। 2,4-डी के छिड़काव के समय ध्यान दें कि आस-पास कपास की फसल न हो।
* जुलाई-अगस्त के दौरान गाजरघास संक्रमित क्षेत्रों में जैविक कीट नियंत्रण के लिए मेक्सिकन बीटल (जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा) को छोड़ें। इस कीट का लार्वा और वयस्क पत्तियों को खाकर पौधे को नष्ट कर देते हैं।

जन-सामान्य में गाजरघास उन्मूलन और इस खरपतवार से होने वाली स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान केन्द्र द्वारा प्रति वर्ष 16-22 अगस्त 'गाजरघास जागरूकता सप्ताह' मनाया जाता है।

किसानों को गेहूं – धान के चक्र से बाहर निकलने में मदद को कई सुविधाएं

शेड नेट हाउस के लिए 14.2 लाख प्रति एकड़ वर्मी कम्पोस्ट यूनिट को 50 हज़ार की सब्सिडी

फसल विविधता अपनाने तथा किसानों को रिवायती फसल-चक्र से बाहर निकालने के लिए पंजाब सरकार राज्य में बागवानी को बढ़ावा दे रही है। इसके तहत एन.एच.एम. (राष्ट्रीय बागवानी मिशन) के अधीन किसानों को बागवानी से संबंधित प्रोजैक्ट स्थापित करने के लिए सब्सिडी मुहैया करवाई जा रही है। बागवानी विभाग ने किसानों से इस स्कीम का अधिक से अधिक फायदा लेने के लिए आवेदन करने की अपील की।

इस स्कीम के अधीन नया बाग लगाने के लिए 19 से 20 हज़ार रुपए प्रति हैक्टेयर, पुराने बागों को पुनर्जीवित करने के लिए 20 हज़ार रुपए प्रति हैक्टेयर, शेड नेट हाउस के लिए 14,20,000 रुपए प्रति एकड़, वर्मी कम्पोस्ट यूनिट के लिए 50 हज़ार रुपए प्रति यूनिट, मधुमक्खी पालन के लिए 1600 रुपए प्रति बक्सा समेत 8 फ्रेम मक्खी, मशीनरी जैसे पॉवर टिलर, स्प्रे पम्प आदि पर 40 फीसदी सब्सिडी, हाईब्रिड सब्जियां उगाने के लिए 20 हज़ार रुपए प्रति हैक्टेयर, प्लास्टिक टनल्स के लिए 30 हज़ार रुपए प्रति 1000 वर्ग मीटर, प्लास्टिक मलचिंग के लिए 16 हज़ार प्रति हैक्टेयर, बाग तथा सब्ज़ियों की तुड़ाई के बाद इसकी संभाल और पैकिंग के लिए पैक हाउस बनाने को 2 लाख रुपए, कोल्ड स्टोर तथा राइपनिंग चैंबर बनाने के लिए 35 फीसदी सब्सिडी दी जा रही है।

स्टेट प्लान स्कीम के अधीन भी 50 फीसदी तक सब्सिडी

इसके अलावा पंजाब सरकार भी राज्य में बागवानी को प्रोत्साहित करने को स्टेट प्लान स्कीम चला रही है। इसके अधीन 30 गुणा 60 फीट बैंबू हट मशरूम कल्टीवेशन के लिए 80 हज़ार, फूलों का बीज तैयार करने को 14 हज़ार प्रति एकड़, 10 किलोग्राम क्षमता वाले दो कार्टन बॉक्स पर 20 रुपए प्रति बॉक्स और 21 किलो क्षमता वाले प्लास्टिक करेट पर 50 रुपए प्रति करेट सब्सिडी, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अधीन लगे पॉली हाउस/पॉली नेट हाउस की शीट बदलने पर 50 फीसदी सब्सिडी मुहैया करवाई जाती है। एक माली को 200 क्रेट तक यह सब्सिडी मिल सकती है।

स्कीम का लाभ लेने के लिए बागवानी दफ्तर से करें सम्पर्क

बठिंडा बागवानी विभाग के डिप्टी डायरैक्टर गुरशरण सिंह के अनुसार एन.एच.एम. स्कीम के तहत किसानों को बागवानी से संबंधित प्रोजैक्ट लगाने के लिए 35 फीसदी सब्सिडी तथा स्टेट प्लान स्कीम के अधीन 50 फीसदी तक सब्सिडी मिल रही है। इन स्कीमों का लाभ लेने के लिए किसान बागवानी दफ्तर से सम्पर्क कर सकते हैं। वहीं, मोगा बागवानी विभाग के सहायक डायरैक्टर विजय प्रताप के मुताबिक, मौजूदा योजनाओं के अलावा सरकार ने वर्ष 2024-25 के दौरान पानी और बिजली बचाने के लिए कुछ नई योजनाएं भी शुरू की हैं।

खेती दुनिया

KHETI DUNIYAN

मुख्य कार्यालय

के.डी. कॉम्पलैक्स, गऊशाला रोड, नजदीक शेरे पंजाब मार्केट, पटियाला - 147001 (पंजाब)

फोन : 0175-2214575

मो. 90410-14575

E-mail : khetiduniyan1983@gmail.com

वर्ष : 08 अंक : 35

तिथि : 31-08-2024

सम्पादक

जगप्रीत सिंह

मुख्य शाखाएं

पटियाला

फोन : 0175-2214575

मो. 90410-14575

मुम्बई

दिल्ली

लुधियाना

बण्ठिडा

सम्पादकीय बोर्ड

डॉ. डी.डी. नारंग

डॉ. जे.एस. डाल

डॉ. आर.एम. फुलझेले

कम्पोजिंग

एक्ता कम्प्यूटरज़ पटियाला

Editor, Printer & Publisher **JAGPREET SINGH**
Printed at **Vargenia Printers**, Sher-e-Punjab Market, Gaushala Road, PATIALA &
Published at Patiala for Prop. **JAGPREET SINGH**

5 महिलाओं ने बनाया ग्रुप, उपलब्ध करवा रहीं मोटे अनाज की वस्तुएं

बरनाला ज़िले के भोतना गांव की पांच महिलाओं ने 10 साल पहले सुखमणि सेल्फ हैल्प ग्रुप बनाया। वे इस ग्रुप के जरिये लोगों को सेहतमंद खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवा रही है, मुनाफा कमा रही है और समाज को भी एक संदेश दे रही हैं। उनका मकसद है कि लोग मोटे अनाज से बने अपने पुराने खाने की ओर लौटें, ताकि कई गंभीर बीमारियां अपने आप खत्म हो सकें। सेल्फ हैल्प ग्रुप चलाने वाली महिलाओं अमरजीत कौर, नरेन्द्र पाल कौर, हरविंदर कौर, गुरप्रीत कौर और कर्मजीत कौर के अनुसार, वे करीब 10 साल से इस काम में लगी हुई है। साल 2016 में उन्होंने यह ग्रुप रजिस्टर्ड करवाया था। तबसे वे सरस मेलों, लोकल मेलों आदि में अपने स्टॉल लगाती आ रही है। लोग उनके घरों में आकर उत्पाद खरीद ले जाते है।

पहले खेती विरासत मिशन से जुड़ीं, फिर अपना ग्रुप बनाया

अमरजीत कौर ने बताया कि वे पहले ऑर्गेनिक खेती पर काम करने वाली संस्था खेती विरासत मिशन से जुड़ी थी। तब उन्होंने लोगों को किचन गार्डन का नया कॉन्सेप्ट दिया था कि अपने घर में एक थोड़ी-सी खाली जगह पर ऑर्गेनिक तरीके से नींबू, मिर्च, टमाटर, मौसमी सब्ज़ियां कैसे लगा सकते हैं, ताकि परिवार को हर रोज़ लगभग 200 रुपए की बचत हो सके और साथ ही केमिकल से रहित पौष्टिक खाद्य पदार्थ भी मिल सकें। इसके बाद उन्होंने एक सर्वे में हिस्सा लिया, जिससे उन्हें पता चला कि प्रदेश में ब्लड प्रैशर, शूगर, कैंसर, बाल सफेद होना, आंखों की रोशनी कमज़ोर होना। इन सबका कारण है कि हम मोटा अनाज ज्वार, मक्की, बाजरा आदि खाना छोड़ कर मैदा खाने लगे हुए हैं। इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि अब वे लोगों को सेहतमंद बनाएंगी और मेहनत करके रुपए भी कमाएंगी। उन्होंने ज्वार, मक्की, बाजरा आदि से खाद्य उत्पाद बनाने शुरू किए। बाज़ार में जिस तरह पीजा का बेस मैदे का मिलता है, वह उसे बाजरा और मक्की से तैयार करती है, जो अधिक सेहतमंद और स्वादिष्ट होता है। इसके साथ वे बिस्किट, मट्ठी समेत कई वस्तुएं मोटे अनाज से ही तैयार करती हैं। इसके अलावा उनके पास मौसम के अनुरूप अचार होता है। वे लाइव फूड बनाकर भी बेचती हैं, जिसमें मक्की की रोटी, सरसों का साग, सोयाबीन की सब्ज़ी, मशरूम की सब्ज़ी आदि तमाम पदार्थ शुद्ध होते हैं। वह कई राज्यों केरल, कर्नाटक के बड़े शहरों के साथ मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, आगरा आदि में अपने स्टॉल लगा चुकी है।

तेज बरसात, आंधी से धान की अगेती फसलों को भारी नुकसान

गत् दिनों हरियाणा में हुई तेज़ बरसात और आंधी के कारण धान की अगेती फसलों को नुकसान हुआ है। धान की 1509 व 1692 किस्म खेतों में बिछ गई है। इसका सीधा असर पैदावार पर होगा।

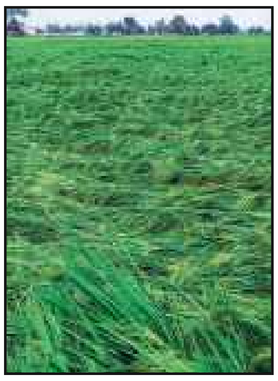

मूसलाधार बारिश से क्षेत्र में लगी अगेती किस्म के धान को नुकसान हुआ है। सीवन क्षेत्र के किसान राजेश रहेजा, जरनैल सिंह, सुरेन्द्र सरदाना, हरपाल सैनी, सुरेश नरेन्द्र सैनी, सतीश सैनी व अन्य ने बताया कि सीवन व आस-पास के क्षेत्र में काफी संख्या में किसानों ने अगेती धान लगाई हुई है, जिससे 1509 व 1692 किस्म शामिल है। बरसात के बाद काफी क्षेत्र में धान की यह किस्में बिछ गई हैं। इसके अलावा धान की दूसरी किस्मों को भी नुकसान हुआ है, जो अब निसारे पर थी या जिनकी बालियां निकल रही थी। इस बरसात के कारण धान का दाना काला हो जाएगा, जिससे किसानों को नुकसान होगा। किसानों ने बताया कि जिन किसानों ने अगेती सब्ज़ी की तैयारी करनी थी या नेट हाउस में खीरा, टमाटर व शिमला मिर्च लगानी थी, वह भी कम से कम 15 दिनों के लिए काम रुक गया है। यह काम अब दो सप्ताह के बाद शुरू होगा। आगे भी बरसात होती है, तो नुकसान बढ़ सकता है।

कृषि उत्पाद का निर्यात 50 हज़ार करोड़ बढ़ाने का प्लान कर रही यू.पी. सरकार

उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कृषि और बागवानी क्लस्टर बनाने की योजना पर काम कर रही है। इसके तहत उसने अगले तीन से चार वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए के कृषि निर्यात करने का टारगेट सेट किया है। की एक सीरीज के लिए नए क्लस्टर बना रहा है। इसके अलावा, राज्य कॉमन फैसिलिटि सैंटर (सी.एफ.सी.) के माध्यम से ग्रेडिंग, पैकिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए प्रमुख वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ओ.डी.ओ.पी.) खेती के तहत जिलों को उन्नत कर रहा है। साथ ही प्रयागराज से हल्दिया तक

हालांकि वर्तमान में राज्य का सालाना कृषि निर्यात लगभग 20,000 करोड़ रुपए का है। जानकारों का कहना है कि सरकार की इस कोशिश से किसानों को काफी फायदा होगा और निर्यात बढ़ने से किसानों की कमाई भी बढ़ेगी।

9 इलाकों में बनेंगे क्लस्टर

एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार बागवानी निर्यात की क्वालिटी बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार के 1,800 करोड़ रुपए के क्लीन प्लांट प्रोग्राम का लाभ उठाने की योजना बना रही है। यू.पी. सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि क्लस्टर बनाने के लिए 9 इलाकों को चुना गया है, जिसमें गंगा का मैदानी इलाका भी शामिल है। उन्होंने कहा कि यू.पी. में कृषि को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी है। ऐसे में हम केन्द्रीय योजनाओं से लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में हैं।

जलमार्ग से कृषि वस्तुओं का ढुलाई

उन्होंने कहा कि क्लस्टर खेती से कृषि में एक नई क्रांति आएगी। इससे किसानों की कमाई में बढ़ोत्तरी होगी। उनके मुताबिक राज्य मौजूदा कृषि क्लस्टरों को विकसित कर रहा है। साथ ही फलों और फसलों जलमार्ग के माध्यम से कृषि वस्तुओं की ढुलाई की जा रही है।

जेवर हवाई अड्डे से बाहर भेजे जाएंगे कृषि उत्पाद

वहीं आने वाले वर्षों में जेवर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से भी पश्चिमी यू.पी. के कृषि उत्पादों को निर्यात करने में मदद मिलेगी।

केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान (सी.आई.एस.एच.) के निदेशक टी. दामोदरन ने कहा कि संस्थान ने लखनऊ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दशहरी और चौंसा आम की किस्मों के लिए क्लस्टर स्थापित किए हैं, जिससे लगभग 4,000 बागवानों को लाभ हुआ है।

यह पहल उत्तर प्रदेश कृषि विकास और ग्रामीण उद्यम पारिस्थिति की तंत्र को मज़बूत करने का एक हिस्सा है। पहली बार मलीहाबाद (लखनऊ) से 5 टन दशहरी आम की खेप संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात की गई है।

अगर पूरे देश की बात करें तो भारत ने साल 2022-23 में 355 मिलियन टन बागवानी फसलों की कटाई की, जबकि 2023-24 में 15,000 करोड़ रुपए के ताज़े फलों और सब्ज़ियों का निर्यात किया।

पक्षियों द्वारा धान की फसल में कीट नियंत्रण

ललिता, सुमित सैनी, विशाल गांधी व चरण सिंह,
सहायक वैज्ञानिक, चौ. चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय,
चावल अनुसंधान संस्थान, कौल–136021

धान की फसल में पक्षियों द्वारा कीट नियंत्रण एक प्राकृतिक और प्रभावी तरीका हो सकता है। यह एक बायोलॉजिकल कंट्रोल का उदाहरण है, जो खेती में जल्दबाजी और पर्याप्त प्रदूषण से बचने में मदद करता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल के तहत पक्षियों को खेत में आने देना और खेत के कीटों को खाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना होता है।

पक्षियों द्वारा कीट नियंत्रण एक सकारात्मक और प्राकृतिक उपाय है, जो खेती में पर्याप्त प्रदूषण के साथ संबंधित समस्याओं को कम करने में मदद करता है। धान की फसल में पक्षियों द्वारा कीट नियंत्रण एक प्राकृतिक और प्रभावी तरीका हो सकता है। यह एक बायोलॉजिकल कंट्रोल का उदाहरण है, जो खेती में जल्दबाजी और पर्याप्त प्रदूषण से बचने में मदद करता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल के तहत पक्षियों को खेत में आने देना और खेत के कीटों को खाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना होता है। इसके लिए निम्नलिखित तरीके भी है, जिनसे आप पक्षियों द्वारा कीट नियंत्रण को बढ़ा सकते हैं।

* पक्षियों को खेतों में आने के लिए अच्छे से संरक्षित पर्यावरण बनाएं। जल बोध खेतों, वन्य जीवन अभ्यारण्य, बागवानी खेत, खाद्य स्त्रोत और पानी के प्रत्यावर्तन क्षेत्र जैसे स्थानों का उपयोग पक्षियों को खेतों में आकर्षित करने में मदद करेगा।

* खेतों में पेड़-पौधों को लगाने से पक्षियों को आवास और आहार के लिए अधिक संभावनाएं मिलती हैं। खेतों में पेड़-पौधों के साथ सही वन्यजीवन भी आता है, जो कीटों को नियंत्रित कर सकता है। खेतों के पास पक्षियों के लिए आहार प्रदान कीटों का नियंत्रण करने में मदद करती है।

* खेतों में जलावतरण बनाने से पक्षियों को प्यास बुझाने के लिए एक स्थायी स्तर पर पानी की उपलब्धता मिलती है। इससे उन्हें खेतों में ज्यादा समय तक ठहरने की सुविधा होती है और उन्हें कीटों को खाने का अधिक मौका मिलता है।

* खेतों के चारों ओर प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र बनाएं। यह उन्हें आरामदायक और सुरक्षित स्थान प्रदान करता है। जहां वे अपने आहार की खोज और खेत के कीटों के शिकारी बन सकते हैं।

* प्राकृतिक छाया और पानी की स्थापना करने से पक्षियों का आकर्षण बढ़ता है। यह उन्हें खाने के स्थल की पहुंच प्रदान करता है और उनके साथ कीटों का नियंत्रण करने में मदद करता है।

* अधिक पक्षियों को खेती में आकर्षित करने के लिए लोकल प्रकृति पक्षी अभ्यारण्य या संगठनों को समर्थन कर सकते हैं, जो पक्षियों की संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए प्रयास कर रहे हैं। अधिक पक्षियों को खेत में आकर्षित करने के लिए नियमित खेत संरक्षण कार्यक्रम आयोजित करें। इनमें खेतों में बहुत सारे आकर्षित पौधों को उगाना शामिल हो सकता है।

* खेतों में उपलब्ध कीटनाशकों का प्रयोग करने के बजाय बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए पक्षियों का उपयोग कर सकते है। कीटनाशकों का उपयोग करने से पक्षियों के लिए खतरा होता है और वे खेत में कीटों को खाने में कम रुचि दिखाएंगे।

* खेतों में पक्षियों के अधिक संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए ये आसान उपाय आपके लिए मददगार साबित हो सकते है। इन तरीकों के साथ आप अपने खेतों को प्रभावी और प्राकृतिक ढंग से पूर्वाही कर सकते हैं और उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं।

* कुछ पक्षियों को पालने वाले संगठन और सरकारी अभियांत्रिकी प्रोग्रामों का समर्थन करें, जो पक्षियों के संरक्षण को प्रोत्साहित करते हैं। इन प्रोग्रामों में पक्षियों को पाल कर उन्हें खेतों में छोड़ा जा सकता है, जिससे वे कीट नियंत्रण के लिए मदद कर सकते हैं।

* खेती में पक्षियों द्वारा कीट नियंत्रण तकनीकों को समझने में समय लग सकता है, लेकिन इसके लिए चिंता करने की जरुरत नहीं है धीरे-धीरे नई तकनीकें सीखने और अपनाने का प्रयास करें, ताकि आप खेती में प्राकृतिक रूप से कीट नियंत्रण कर सकें और पक्षियों के माध्यम से फसलों को सुरक्षित रख सकें।

* स्थानीय किसानों को पक्षियों के महत्व की जागरूकता देने और उन्हें उनके साथ कीटों का सही तरीके से नियंत्रण करने के लिए शिक्षा देना महत्वपूर्ण है। किसानों को यह समझना आवश्यक है कि कौन से पक्षियों कीटों के नियंत्रण में मददगार हो सकते हैं और उन्हें कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है। इन उपरोक्त तरीकों का संयोजन करके किसान स्थायी और प्राकृतिक तरीके से खेत में पक्षियों के माध्यम से कीट नियंत्रण को अधिक सकारात्मक बना सकते हैं व फसल की सुरक्षा और पैदावार में सुधार कर सकते हैं। ❑

"ग्वार पाठा को घृतकधरी के नाम से भी जाना जाता है। इससे अंग्रेजी में एलोवीरा कहते हैं। यह लिलिएसी कुल का औषधीय पौधा है। इसका उत्पत्ति स्थान उत्तरी अफ्रीका माना जाता है। इसमें अनेक औषधीय गुण पाये जाते है जो विभिन्न प्रकार के रोगों के उपचार में आयुर्वेदिक एवं युनानी चिकित्सा पद्धति में उपयोग किया जाता है। इसके औषधीय गुण के कारण इसे बगीचों एवं घरों के समीप भी उगाया जाता है। पहले इसे खेतों के मेंडों पर, नदी किनारे अपने आप उग आता था, परंतु इस की बढ़ती मांग के कारण कृषक व्यवसायिक रूप से खेती कर रहे हैं और समुचित लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसकी विशेषता है कि इसे उर्वर मृदा, कम सिंचाई व कम देखभाल में सुगमता से उगाया जा सकता है।"

कम उर्वरक मृदा में

ग्वार पाठा उगाइए

वानस्पतिक विवरण : ग्वार पाठा के पौधे की सामान्य ऊंचाई 60–90 से.मी. होती है। इसके पत्तों की लम्बाई 30–45 से.मी. और चौड़ाई 2.5–7.5 से.मी. और मोटाई 1.25 सेमी. होती है। प्रारम्भ में इसके पत्ते सफेद रंग के होते है। पत्ते आगे से नुकीले एवं किनारों पर कंटीले होते है। पौधों के बीचों बीच एकदंड पर लाल फुल आते है। इस पर शीतकाल में आते जिन पर फल आते है।

इसकी खेती से अधिक उत्पादन प्रप्त करने हेतु कृषक बन्धुओं को निम्न बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए।

जलवायु : ग्वार पाठा को उष्ण, आद्र एवं समशीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में सरलतापूर्वक उगाया जा सकता है। कम वर्षा और अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में इस की खेती की जा सकती है।

भूमि : ग्वार पाठा को किसी भी प्रकार की भूमि में उगाया जा सकता है। इसे चट्टानी, पथरीली, रेतली भूमि में भी उगाया जा सकता है, किन्तु जलमग्न भूमि में इसका उत्पादन नहीं किया जा सकता है। उचित जल निकास वाली रेतीली दोमट भूमि जिसकी पी.एच. मान 6.5–8.0 के मध्य हो सर्वोत्तम मानी गयी है।

खेत की तैयारी : जिस खेत में ग्वार पाठा की खेती करनी हो उसे सर्वप्रथम खरपतवारों व घासों आदि से मुक्त करना होगा, जिसके लिए ग्रीष्म ऋतु में 2–3 बार जुताई करना नितान्त आवश्यक है। खेत की गहरी जुताई की आवश्यक्ता नही है क्योंकि ग्वार पाठा की जड़ें उथली होती है।

जिस समय ग्वार पाठा की रोपाई करनी हो, उस समय खेत की जुताई करके पाठा लगाकर मिट्टी को भुरभुरा कर खेत में 45 से.मी.–45 से.मी. की दूरी पर मेड़े बना दी जाती है। इन मेंड़ों की ऊंचाई लगभग 30 से.मी. रखनी चाहिए।

खाद एवं उर्वरक : सामान्य तथा ग्वार पाठा की फसल को विशेष प्रकार की खाद एवं उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती है, परन्तु अच्छी वृद्धि एवं उत्पादन के लिए 10–15 टन गोबर की खाद, अंतिम जुताई के समय प्रति हैक्टेयर की दर से डालनी चाहिए। इसके अतिरिक्त 50 किलो नाइट्रोजन, 25 किलो फास्फोरस एवं पोटाश की पूरी मात्रा बुवाई से पूर्वच और शेष नाइट्रोजन की मात्रा 2 माह बाद 2 भागों में बांट कर देनी चाहिए अथवा नाइट्रोजन की शेष मात्रा को 2 बार छिड़काव भी कर सकते है।

प्रवर्धन : ग्वार पाठा का प्रवर्धन छोटे पौधे अथवा साइड सर्कस के द्वारा किया जाता है। यूं तो ग्वार पाठा के पौधों पर बीज भी आते है उनसे भी प्रवर्धन किया जा सकता है, परन्तु यह विधि व्यवसायिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।

वर्ष ऋतु में उपयुक्त नमी की अवस्था में इसके पौधों को 50 सैंटीमीटर × 50 सैंटीमीटर की दूरी पर मेंड़ या समतल खेत में रोपाई की जाती है। कम उर्वरक भूमि में पौधों को 40 सैंटीमीटर × 40 सैंटीमीटर पर रोपाई करनी चाहिए, जिससे पौधों की संख्या 40,000–50,000 प्रति हैक्टेयर पर्याप्त होती है। वैसे इसकी रोपाई का उपयुक्त समय जून–जुलाई है परन्तु सिंचाई की सुनिश्चित व्यवसाीा होने पर इसकी रोपाई फरवरी माह में भी की जा सकती है।

उन्नत किस्में : एलोइन एवं जैल उत्पादन की दृष्टि से नेशनल ब्यूरों ऑफ प्लांट जेनेटिक सोर्सेज द्वारा ग्वार पाठे की उन्नत किस्मों के नाम नीचे दिये गये है : आई. सी. 111271, आई.सी. 111269, आई.सी. 111280, आई.सी. 111273, आई.सी. 111267, आई. सी. 111279 एलोइन की मात्रा की दृष्टि एवं आई.सी. 111267, आई. सी. 111280, आई.सी. 111272, आई.सी. 111277 को जैल की दृष्टि से उत्तम माना जाता है।

सीमेप, लखनऊ द्वारा भी ग्वार पाठे की उन्नत किस्म अंकचा (ए. एल 1) विकसित की गई है।

सिंचाई एवं जल निकास : ग्वार पाठा एक ऐसा पौधा है जो शुष्क मृदाओं में भी उगाया जा सकता है और सिंचित क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है। ग्वार पाठा के पौधों की रोपाई के तुरन्त बाद सिंचाई करनी चाहिए ताकि पौधे भली–भांति स्थापित हो जाए। ग्रीष्म ऋतु में जब गर्मी पूरे जोरों पर हो उस समय इसे एक सिंचाई की आवश्यकता होती है।

यदि वर्षा ऋतु में खेत में पानी एकत्रित हो जाए तो उसे तुरन्त निकालने की व्यवस्था की जानी चाहिए अन्यथा फसल पीली पड़ कर मर जाने की आशंका रहती है।

यदि सिंचाई की सुनिश्चित व्यवसाय न हो तो ग्वार पाठा के पौधों में जैल की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक विकसित होती है। इस प्रकार यदि महीने में एक बार सिंचाई की व्यवस्था हो सके तो पौधों में तैयार होने वाली जैल की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि और उत्पादन भी बढ़ेगा।

सिंचाई जल की बचत करके एवं अधिक उपयोग करने के लिए स्प्रिंकलर या ड्रिप विधि का उपयोग कर सकते है।

फसल की कटाई : इस फसल की उत्पादन क्षमता बहुत अधिक होती है। पौधों की रोपाई के एक वर्ष बाद पत्तियां काटने योग्य हो जाती है। इसके बाद दो माह के अन्तराल पर परिपक्व पत्तियों को काटते रहना चाहिए। पत्तियों को काटने हेतु तेज धार वाले हंसिए का उपयोग करना चाहिए। काटने के उपरान्त पौधे पर पुन: पत्ते उग जाते है। इस प्रकार यह फसल 4–5 वर्ष तक अच्छी उपज देती रहती है। पत्तों को काटने के उपरान्त पौधों पर फफूंदी का प्रकोप हो सकता है अत: फसल पर इन्डोथेन एम–45 का छिड़काव करना चाहिए।

उपज : यदि ग्वार पाठा की उपरोक्त वर्णित विधि से खेती की जाए तो प्रथम वर्ष में 35–40 टन / हैक्टेयर उत्पादन मिल जाता है। द्वितीय वर्ष में 10–15 प्रतिशित उत्पादन बढ़ जाता है। बारानी क्षेत्रों में लगभग 20 टन / हैक्टेयर उत्पादन मिल जाता है।

पौध संरक्षण के उपाय

खरपतवार नियंत्रण

क्योंकि ग्वार पाठा धीमी गति से वृद्धि करने वाला पौधा है अत: रोपाई के प्रथम वर्ष में खेत में अधिक खरपतवार उगाने की सम्भावना रहती है। इन खरपतवारों की सफाई की दृष्टि से खेत की नियमित अंतरालों पर निराई–गुड़ाई करना नितान्त आवश्यक है। निराई–गुड़ाई के समय पौधों पर मिट्टी भी चढ़ा देनी चाहिए।

कीट नियंत्रण

आमतौर पर ग्वार पाठा की फसल पर कोई कीट नहीं लगता है, परन्तु कभी–कभी तनों व जड़ों को ग्रब नामक सूंडी क्षति पहुंचाती है। इसकी रोकथाम के लिए 60–70 किलो नीम की खली/ हैक्टेयर खेत की तैयारी के समय डालनी चाहिए।

रोग नियंत्रण

पत्ती धब्बा रोग : ग्वार पाठा में कभी–कभी आल्टर नेटिया, आल्टानेटा एवं फ्यूजरियम सोलानी नामक कवकों के कारण यह रोग हो जाता है। इस रोग के कारण पौधों की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, साथ ही तैयार होने जैल की गंध भी प्रभावित होती है। इसकी रोकथाम हेतु मैंकोजेब या क्लोरोथेनोल की 3 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए।

भूस्खलन रोकने के लिए जैव विविधता संरक्षण जरूरी

सुनील कुमार महला

वर्तमान में मौनसून का सीज़न चल रहा है। मौनसून के इस सीज़न में कहीं-कहीं बहुत अधिक बारिश हो रही है और इससे जहां एक ओर हमारे देश में अनेक स्थानों पर बाढ़ आ गई है, तो वहीं दूसरी ओर पहाड़ों में भूस्खलन की घटनाएं घटित हो रही हैं। दरअसल आज हम प्रकृति के संरक्षण की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और यही कारण है कि जलवायु परिवर्तन से बारिश भी बहुत अधिक होने लगी है, तो कहीं पर सूखा भी पड़ने लगा है।

बारिश शहरों व बड़े महानगरों से लेकर गांव गलियों तक के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल रहा है। आज बढ़ती जनसंख्या के बीच हमारे शहर भी नियोजित ढंग से नहीं बसाए गए है और उसका

खामियाजा हमें निचले इलाकों में पानी भरने, बाढ़ आने के रूप में देखने को मिल रहा है। हमारे देश में भूस्खलन की घटनाएं तो जैसे आम होने लगी हैं, विशेषकर बारिश के सीज़न में। कहना गलत नहीं होगा कि भूस्खलन का कारण कहीं न कहीं अधिक बारिश भी है। बारिश ही नहीं, बर्फ पिघलने, जल स्तर में परिवर्तन, धारा कटाव, भूजल में परिवर्तन, भूकंप, जलामुखीय गतिविधियों, मानवीय गतिविधियों द्वारा गड़बड़ी, या इन कारकों के किसी भी संयोजन से ढलानों में भूस्खलन शुरू हो सकता है। भूकंप के झटके और अन्य कारक भी पानी के भीतर अनेक बार भूस्खलन को प्रेरित कर सकते हैं। हमारे देश भारत में भूस्खलन एक बहुत ही गंभीर प्राकृतिक आपदा है, जिसके भयानक परिणाम होते हैं। भूस्खलन की घटनाएं खड़ी ढलान वाली भूमि, चट्टानों में जोड़ व दरारें होने, ढीली मिट्टी (वृक्ष कटाई के कारण), चरागाहों के कम होने के कारण होती है। वनों में आग लगने से मिट्टी कमज़ोर पड़ जाती है और वहां भूस्खलन की घटनाएं घटित होने लगती हैं। मानवीय गतिविधियों जैसे वनों की अंधाधुंध कटाई, कंक्रीट के जंगलों में बढ़ोत्तरी (निर्माण कार्य) से भी भूस्खलन होता है। वास्तव में देखा जाए तो भूस्खलन के प्राकृतिक व मानवीय दोनों ही कारण हैं। एक ओर जहां भारी बारिश, भूकंप, मिट्टी का प्राकृतिक रूप से क्षरण, ज्वालामुखी विस्फोट भूस्खलन के प्राकृतिक कारण हैं, वहीं दूसरी ओर खनन, जलवायु परिवर्तन, अतिक्रमण, वनों की कटाई मानवजनित कारणों में से एक है। इन दिनों हमारे देश में दक्षिण-पश्चिमी मौनसून आसमानी आफत का रूप ले चुका है। बीते कुछ दिनों से दक्षिण से उत्तर भारत तक जहां देखो, वहीं पर पानी का रौद्र रूप देखने को मिला। उल्लेखनीय है कि हाल में ही केरल के वायनाड में तीव्र भू-स्खलन ने मुंडक्कई, चूरलमाला कस्बों का अस्तित्व तक ही मिटा दिया।

भीषण त्रासदी में सैंकड़ों लोग मारे गए। पशुधन, जान माल को काफी नुकसान पहुंचा है। जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। सच तो यह है कि विनाशकारी लैंडस्लाइड अब राष्ट्रीय आपदा बन चुकी है। केरल जैव विविधता की दृष्टि से भारत के सम्पन्न राज्यों में से एक है, ऐसे में केरल जैसे राज्य में लगातार भूस्खलन चिंता का विषय है। अध्ययन बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन और वन क्षेत्र की हानि केरल के वायनाड में विनाशकारी भूस्खलन के दो महत्वपूर्ण कारण हैं। इसरो की सैटेलाइट तस्वीरें वायनाड भूस्खलन में व्यापक तबाही दिखाती हैं। सैटेलाइट द्वारा प्राप्त तस्वीर से पता चलता है कि लगभग 86,000 वर्ग मीटर भूमि खिसक गई, जिससे राष्ट्रपति भवन के आकार से लगभग पांच गुना बड़ा भूस्खलन हुआ। पता चला है कि मलबा इरुवैफुझा नदी के किनारे लगभग 8 किलोमीटर तक बह गया, यह बहुत ही चिंताजनक है।

जानकारी देना चाहूंगा कि इसरो द्वारा तैयार किए गए 2023 लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया ने वायनाड क्षेत्र को भूखलन के प्रति संवेदनशील क्षेत्र के रूप में रखा था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इसरो के बीते वर्ष जारी भूस्खलन मानचित्र के मुताबिक, भारत के 30 सर्वाधिक भूस्खलन-संभावित जिलों में से 10 केरल में ही थे और वायनाड इनमें 13वें स्थान पर था। इसी में यह भी कहा गया था कि पश्चिमी घाट का 90 हज़ार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील है। आज भारत ही नहीं, सम्पूर्ण विश्व में जलवायु परिवर्तन तेज़ी से हो रहा है। गर्मियों में गर्मी अधिक और सर्दियों में सर्दी अधिक, कहीं न कहीं जलवायु परिवर्तन का ही प्रभाव है, ऐसे में आज हम सभी को चेतने की जरूरत है।

कृषि नवाचार में डिजिटल पहल

रघुवीर चारण

आज विश्व के हर क्षेत्र में तकनीक का बोलबाला है। तकनीकी नवाचार ने पिछले कुछ वर्षों में दुनिया को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने हमारे जीवन को सरल और अधिक उत्पादक बना दिया है। वर्तमान तकनीकी परिदृश्य में सबसे आकर्षक विकासों में से एक ए.आई. यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसमें स्वास्थ्य सेवा, अंतरिक्ष और कृषि क्षेत्रों में क्रांति लाने की अपार क्षमता है। हाल ही में आज़ादी के अमृतकाल की 78वीं वर्षगांठ के अवसर पर केन्द्र सरकार द्वारा ए.आई. आधारित राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का शुभारंभ हुआ। राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली एक डिजिटल पोर्टल है, जिसका उद्देश्य किसानों और कृषि वैज्ञानिकों के साथ समन्वय स्थापित कर बेहतर कीट प्रबंधन प्रदान करना है।

इस पहल में मोबाइल एप्प और वैब पोर्टल शामिल है, जिसमें वास्तविक समय का डेटा और उन्नत विश्लेषणों की मदद से ये एप्प सटीक कीट की पहचान, निगरानी और प्रबंधन की सुविधा प्रदान करेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि देश की आधी आबादी कृषि पर निर्भर है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आजीविका का आधार है, हालांकि बढ़ती जनसंख्या खाद्यान्न की उच्च मांग से देश का कृषिक्षेत्र कई चुनौतियों से जूझ रहा है, उनमें से जलवायु परिवर्तन, मिट्टी की उर्वरता में कमी और कीटनाशकों से निपटने के लिए रासायनिक उर्वरक पर निर्भरता प्रमुख है। बीते कुछ सालों में कृषि के बदलते स्वरूप से इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी अर्थात् आधुनिक तकनीक की मांग बढ़ी है, जो खेती को आसान व सुलभ बना कर दोगुनी उत्पादकता में सहायक है। सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में नवाचार लाने के लिए समय-समय पर कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया। इसमें कीट नियंत्रण, फसलों का विविधीकरण, सब्सिडी प्रदान करना और खाद्यान्न को सुरक्षित बाज़ार तक पहुंचाना शामिल है। सरकार

कालक्ष्य उत्पादन बढ़ाना, खेती की लागत घटाना, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना व जलवायु अनुकूल किस्मों का विकास करना है।

वर्ष 1988 में सर्वप्रथम एकीकृत कीट प्रबंधन कार्यक्रम की शुरूआत हुई, जिसका उद्देश्य फसल की बुवाई से लेकर कटाई तक हानिकारक कीटों एवं बीमारियों से बचाना तथा किसानों को एक से अधिक तरीकों को जैसे व्यवहारिक, यांत्रिक, जैविक तथा रासायनिक नियंत्रण इस तरह से क्रमानुसार यथायोग्य प्रयोग में लेना, जिससे पर्यावरण नुकसान कम से कम हो। कृषि क्षेत्र में फसलों को कीटों से बचाना एक मुख्य चुनौती है। पिछले कुछ दशकों में कृषि के औद्योगिकीकरण से रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग अंधाधुंध होने लगा, जिसके परिणामस्वरूप दूषित भूमि, मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव और पर्यावरण असंतुलन देखने को मिला। अब वक्त है कीट उन्मूलन की बजाय कीट प्रबंधन को बढ़ावा मिले।

हानिकारक कीटों से बचाव के लिए जैविक तरीकों को अपनाया जाए, जैविक नियंत्रण विधि अर्थात् नाशीजीव के प्राकृतिक शत्रुओं की पहचान कर उसका संवर्धित पोषण करके कीटनाशकों पर छोड़ा जाता है, जो केवल अपने लक्ष्य पर प्रहार करते हैं। इससे मनुष्य, पशु-पक्षियों और पर्यावरण पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता। केन्द्रीय कृषि मंत्रालय की कीट प्रबंधन पर डिजिटल पहल यदि धरातल पर सही सिद्ध होती है, तो भारतीय कृषि के नवाचार में ऐतिहासिक कदम होगा। कीट नियंत्रण में मुख्य समस्या सटीक कीट की पहचान व उचित कीटनाशक का चयन और उसकी मात्रा का है। किसानों को इसके बारे जागरूक कर समय पर अवगत करवाने से फसलों की बर्बादी कम होगी। किसानों की कीटनाशकों के प्रति आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। फसलों को बुवाई से लेकर कटाई तक रोग मुक्त वातावरण मिलेगा।

3 साल से फसल अवशेष को नहीं लगाई आग, प्रगतिशील किसान के तौर पर हुआ सम्मान

कनाडा पी.आर. की फाइल रिजेक्ट होने के बाद युवा किसान ने खेती माहिरों के सुझाए बीजों से गेहूं और धान की फसल से कम लागत में बढ़िया मुनाफा कमाया। किसान प्रत्येक साल खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी के सुझाव अनुसार खेती कर रहा है। तीन साल से फसल के अवशेष को आग नहीं लगाई। घर में ही सोलर प्लांट और गोबर गैस प्लांट लगाया है। इस गोबर गैस प्लांट से तैयार खाद को खेतों में इस्तेमाल कर रहा है। खुद के लिए ऑर्गेनिक गन्ना, सब्ज़ी उगाने के साथ मिनी बाग भी लगाया हुआ है। इसी सप्ताह दिल्ली में समारोह के दौरान गुरिंदर पाल सिंह को अग्रणी किसान के तौर पर सम्मानित किया गया है।

भवानीगढ़ निवासी किसान गुरिंदर पाल सिंह (44) ने बताया कि एम.ए. करने के बाद उन्होंने प्राइवेट नौकरी करनी शुरू कर दी। कुछ समय बाद उसकी शादी हो गई। 2007 में उसने कनाडा में पी. आर. के लिए फाइल लगाई। लेकिन फाइल रिजेक्ट हो गई। जिस कारण उसने पिता के साथ ही खेती में हाथ बंटाने का मन बनाया। सबसे पहले उन्होंने यंग फार्मर रखड़ा से सम्पर्क किया। जिसके बाद वह कृषि विज्ञान केन्द्र, खेड़ी के एसोसिएट डायरैक्टर डॉ. मनदीप सिंह के सम्पर्क में आए। खेती के हर पहलू की बारीकी के साथ जानकारी हासिल की। खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी के सुझाए गए बीजों से ही उसने गेहूं व धान की खेती करनी शुरू कर दी।

प्रदर्शनियों में ले रहे बढ़–चढ़ कर हिस्सा

वह खेतीबाड़ी विभाग द्वारा देशभर में लगाई जाने वाली प्रदर्शनियों में भाग लेने लगा। उसने अपने खेत में ही घर बनाया हुआ है। गैस के लिए गोबर गैस प्लांट लगाया और बिजली के लिए सोलर प्लांट लगाया है। पिछले तीन साल से उसने कभी भी फसल के अवशेष को आग नहीं लगाई। अब तक उसे खेतीबाड़ी विभाग समेत विभिन्न राजनेताओं की ओर से करीब 20 बार सम्मानित किया जा चुका है। मौजूदा समय में खतीबाड़ी करने के लिए शिक्षित होना काफी जरूरी है। यदि यूनिवर्सिटी के खेतीबाड़ी माहिरों के अनुसार खेती की जाए, तो खर्च कम कर बढ़िया मुनाफा कमाया जा सकता है।

बारिश ने धोया नरमे पर सफेद मक्खी का हमला, नरमा पट्टी में स्थिति नियंत्रित

पंजाब की नरमा पट्टी के कई इलाकों में किसान फसल पर सफेद मक्खी और गुलाबी सुंडी के चुनिंदा हमलों से परेशान हैं। खेतीबाड़ी विभाग की टीमें नुकसान का जायजा लेने के लिए सर्वेक्षण में जुटी है। बठिंडा, फाज़िल्का ज़िलों में कुछ असर तो है, लेकिन वे आश्वास्त हैं कि अभी खतरा नहीं है। स्थिति नियंत्रण में है। हालिया बारिश ने नरमे पर सफेद मक्खियों को खत्म कर दिया है। इसलिए किसानों को फसल का नियमित सर्वेक्षण करने के प्रति लगातार जागरूक किया जा रहा है।

हालिया बारिश से नरमे की फसल को काफी फायदा हुआ है। इससे सफेद मक्खी के हमले से कुछ हद तक राहत मिली है, लेकिन गुलाबी सुंडी के हमले से सचेत रहने की जरूरत है। फरीदकोट के मुख्य कृषि अधिकारी डॉ. अमरीक सिंह के अनुसार, ज़िले में लगभग 325 हैक्टेयर में नरमे की खेती की गई है। विभाग का लक्ष्य फसल को कीटों विशेषकर गुलाबी सुंडी से बचाना और अगले वर्ष नरमे का क्षेत्रफल बढ़ाना है। बुवाई के बाद मौसम शुष्क रहने के कारण फसल की वृद्धि अच्छी नहीं थी, लेकिन पिछले दिनों हुई बारिश के कारण फसल की वृद्धि होने के साथ परिस्थितियां भी अच्छी है। सफेद मक्खी का हमला नुकसान की सीमा से कम है और स्थिति नियंत्रण में है। अगले 2-3 सप्ताह फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण

• अगले 2-3 हफ्ते सतके रहने की जरूरत : डॉ. अमरीक
• बठिंडा में फसल का विकास बढ़िया : बलजिंदर सिंह

है। फिलहाल गुलाबी सुंडी का प्रकोप कहीं देखने को नहीं मिला। लेकिन फसल में जहां सेक्स फेरोमोन ट्रैप लगाए गए है, वहां कहीं-कहीं गुलाबी सुंडी के कुछ कीट देखे गए हैं। इसके प्रति नरमा उत्पादकों को अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। विभाग की 12 सर्कल, 2 ब्लॉक और एक ज़िला स्तरीय कृषि विशेषज्ञ टीमें सोमवार और गुरुवार को नरमे की फसल का लगातार सर्वेक्षण कर रही है। ये किसानों के लगातार सम्पर्क में है। उनके अनुसार, किसानों को अपने खेतों में गुलाबी सुंडी के हमले के प्रति लगातार सर्वेक्षण करते रहना चाहिए। वे कीड़ों के हमले के संबंध में किए जा रहे सर्वेक्षण के दौरान कृषि अधिकारियों का पूरा सहयोग करें। नरमे की फसल की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पोटाशियम नाइट्रेट के 4 छिड़काव साप्ताहिक अंतराल पर करें। यदि कोई समस्या आती है, तो कृषि विशेषज्ञों से सम्पर्क करने के बाद ही कीटनाशकों का छिड़काव करना चाहिए।

बठिंडा ब्लॉक के कृषि अधिकारी बलजिंदर सिंह नंदगढ़ के मुताबिक, बठिंडा में स्थिति नियंत्रण में है, जो आर्थिक कगार से नीचे है। बारिश के बाद सफेद मक्खी नाममात्र रह गई है। फसल का विकास भी बढ़िया है। किसानों ने कीटनाशकों का स्प्रे शुरू कर दिया है।

धान-बासमती पर न करें प्रतिबंधित कीटनाशकों का प्रयोग : गुरनाम सिंह

मुक्तसर के मुख्य खेतीबाड़ी अधिकारी गुरनाम सिंह ने बताया कि नरमे की फसल को कामयाब करने के लिए बठिंडा ज़िले में गांव स्तर पर किसान सिखलाई कैंप लगाए जा रहे हैं। इनमें खरीफ विशेषकर नरमे की फसल आ रही समस्याओं व इनके हल के लिए जानकारी दी जा रही है। इस मौके पर जी धान व बासमती की फसलों पर भी कीटों व बीमारियों की रोकथाम के संबंध में भी अवगत करवाने के साथ-साथ बासमती की मियारी पैदावार के लिए प्रतिबंधित कीटनाशक दवाईयों का प्रयोग नहीं करने की भी अपील की जा रही है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे अपने नरमे वाले खेतों का रोज़ाना सर्वेक्षण करें। अगर फसल पर रस चूसने वाले कीड़े या गुलाबी सुंडी का हमला ई.टी.एल. से अधिक आता है, तो वह विभाग के साथ तालमेल करके ही स्प्रे करें।

खेती दुनिया

द्वारा

किसान भाईयों व डीलर/डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए

चंदों में विशेष छूट

एक वर्ष 400/- रुपए

दो वर्ष 700/- रुपए

KHETI DUNIYAN
TID - 62763351

चंदे भेजने हेतु QR कोड सकैन करें।

पेमेंट करने के पश्चात् अपना डाक पता इस नंबर पर भेजें :
90410-14575

एक पेड़ की कीमत

- एक सामान्य पेड़ साल भर में करीब 20 किलोग्राम धूल सोखता है।
- हर साल करीब 700 किलोग्राम ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है।
- प्रति वर्ष 20 टन कार्बन डायऑक्साइड को सोखता है।
- गर्मियों में एक बड़े पेड़ के नीचे औसतन चार डिग्री तक तापमान कम रहता है।
- 80 किलोग्राम पारा, लीथियम, लेड आदि जैसे ज़हरीली धातुओं के मिश्रण को सोखने की क्षमता।
- हर साल करीब 1 लाख वर्ग मीटर दूषित हवा फिल्टर करता है।
- घर के करीब एक पेड़ अकॉस्टिक वॉल की तरह काम करता है। यानी शोर/ध्वनि को सोख लेता है।

घर के पास 10 पेड़ हैं तो जीवन 7 साल बढ़ सकता है

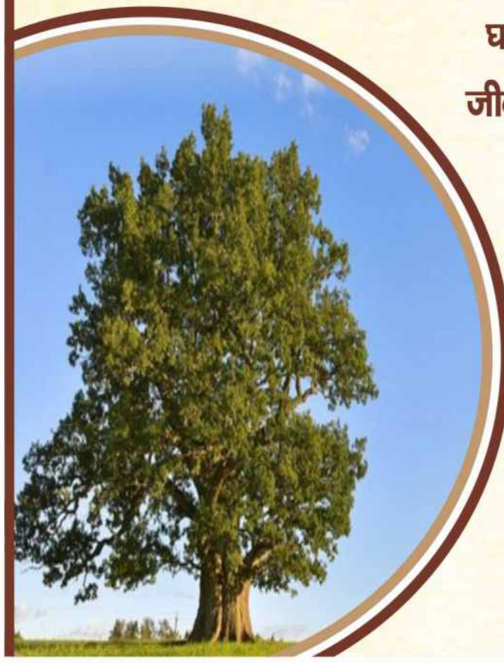

- विन्कॉसिन विश्वविद्यालय ने अध्ययन में बताया है कि जिनके घरों के पास पेड़ होते हैं, उनको तनाव और अवसाद की आशंका कम होती है।
- कैनेडा के जर्नल साइंटिफिक रिपोर्ट्स के अनुसार घर के पास अगर 10 के करीब पेड़ हैं जो जीवन 7 साल बढ़ सकता है।
- इलिनॉय यूनिवर्सिटी ने रिसर्च में बताया है कि घर के पास पेड़ हैं तो नींद अच्छी आती है। विशेषकर वृद्धावस्था में।